मंडियों में मिलर्स की मनमानी, खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं किसान

धान का 1450 रुपए का भाव नहीं मिलता, नमी के नाम पर काटे जा रहे मनमाने पैसे

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

हरियाणा में सबसे पहले धान की सरकारी खरीद शुरू करने और 1509 वैरायटी की भी 1450 रुपए के हिसाब से समर्थन मूल्य दिलाने के लिए राज्य की भाजपा सरकार खुद ही अपना गुणगान कर रही है। लेकिन मंडियों में आने वाला किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसकी वजह यह है कि किसान मंडी में धान की फसल लेकर तो आ जाता है, लेकिन उसे 1450 रुपए का भाव नहीं मिलता है। यहां उसे वैरायटी और नमी के नाम पर 75 से 150 रुपए प्रति क्विंटल तक काम दाम मिल पा रहा है। रोचक बात यह है कि उसे मीटर लगाकर चैक भी नहीं करवाया जा रहा है कि वास्तव में नमी की मात्रा कितनी है। आढ़ती और मिलर्स अंदाज के आधार पर नमी की ज्यादा मात्रा बताकर धान खरीद रहे हैं। अगर किसान इसमें आनाकानी करता है तो उसकी फसल दो-तीन दिन तक मंडी में खुले में पड़ी रहती है। मौसम खराब होने की आशंका से मजबूरी में किसान जो दाम मिले, उसी पर फसल बेचकर जा रहा है। इस तरह की तमाम शिकायतें मिलने के बाद दैनिक भास्कर ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, जींद, सिरसा समेत कई मंडियों में किसानों से बात करके हालात का जायजा लिया। कुरुक्षेत्र मंडी में तो फसल तुलाई के लिए सरकारी इंतजाम भी नहीं हैं। यहां का कांटा पिछले कई कुछ समय से खराब पड़ा है। ऐसे में किसान को आढ़ती की तोल पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि यह पहली बार हो रहा है जब इस तरह नमी के नाम पर उन्हें कम दाम मिल रहा है।

सरकार ने तय की नमी की मात्रा

इधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि भारत सरकार ने धान में नमी की मात्रा 17 परसेंट तक तय की है। किसान हित में 1-2 प्रतिशत ज्यादा नमी वाली धान भी खरीदी जा सकती है। लेकिन मंडियों में जो धान आ रही है, उसमें नमी की मात्रा 24-25 फीसदी तक आ रही है। सूखने पर इसका वजन कम हो जाता है। मिलर्स का कहना है कि 1 फीसदी ज्यादा नमी पर उन्हें 15 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान होता है, इसलिए मिलर्स यह राशि काट रहा है। ये व्यवस्था कई साल से चली आ रही है, पहली बार ऐसा नहीं है।

यह पैसा आखिर जा कहां रहा है

धान खरीद में किसान के नाम पर बिल तो 1450 रुपए के हिसाब से ही कट रहा है। यानी मिलर्स सरकार से इसी दर का भुगतान लेगा। लेकिन किसान कम पैसा मिल रहा है। बीच का यह पैसा कहां और किसके पास जा रहा है। किसानों के साथ-साथ कांग्रेस भी यह सवाल पूछ रही है।

सीएम खट्टर भी नहीं दे पाए जवाब

करनाल में मंडी विजिट के दौरान शनिवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी किसानों ने धान का पूरा मूल्य नहीं मिलने की शिकायत की। सीएम ने धान की ढेरी में माल उठाकर नमी चैक करवाई तो वह 20 फीसदी निकली। लेकिन किसानों ने जब सीएम से सवाल किया कि अगर उनकी फसल में नमी है और कम भाव पर खरीदी जा रही है तो फिर बिल सरकारी रेट 1450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से क्यों काटा जा रहा है। सीएम के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था।

अभी बारिश नहीं तो नमी कहां से आई

धान में 20 फीसदी नमी बताकर मंडियों में किसानों को ठगा रहा है। फिलहाल कोई बारिश नहीं हुई है तो धान में नमी कहां से आ गई? यह किसान को परेशान करने वाला कदम है। कांग्रेस राज में धान की 1121 और 1509 किस्में 4500 रुपए प्रति क्विंटल बिकती थीं, लेकिन इस साल 1200-1300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही हैं। किसानों की ऐसी दुर्गति भाजपा शासनकाल में हुई है।
- रणदीप सुरजेवाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस

क्या कहते हैं किसान

तीन दिन से नहीं लगी धान की बोली

धान की 1509 किस्म मंडी में लेकर आए तीन दिन हो चुके हैं लेकिन नमी ज्यादा होने का बहाना बनाकर धान की बोली भी नहीं हो रही है। सरकारी खरीद एजेंसियों के संबंधित अधिकारी कभी तो धान में नमी की मात्रा को नमी मापक यंत्र से मापते हैं और कभी यूं ही धान को हथेली में रखकर कह देते हैं कि नमी की मात्रा ज्यादा है।
- सुखदेव सिंह, फतेहाबाद

सरकार और मिलर्स की मिलीभगत है

मैं आज ही मंडी में फसल लेकर आया हूं। सरकारी रेट 1450 होने के बावजूद मुझे 1371 रुपए के हिसाब से धान बेचनी पड़ी है। न कोई मीटर लगाकर नमी चैक करवाता है और न ही पूरा रेट दिया जाता है। हम ज्यादा बोलते हैं तो व्यापारी फसल खरीदने से ही मना कर देते हैं। सब मिले हुए हैं। इसलिए जो दाम मिले, उसी पर फसल बेचनी पड़ रही है।
- रामकुमार, किसान बरना (कुरुक्षेत्र)

धान कितनी भी सूखी हो, पूरा दाम मिलता ही नहीं है

किसान भी धान को कितना भी सुखाकर लाए, लेकिन व्यापारी सरकारी रेट पर कभी खरीदते ही नहीं है। मंडी में शायद ही किसी किसान की फसल पूरे दाम पर बिकी होगी। वह पीआर-123 किस्म की धान लेकर आए हैं, उन्हें इसका दाम 1375 रुपए के हिसाब से मिला है। शिकायत करके भी किसान क्या करे, कार्रवाई तो कोई होती नहीं, बल्कि फसल और कई दिन तक नहीं बिक पाती।
- सतपाल, कमोद (कुरुक्षेत्र)